**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**28.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1898 का उत्तर**

**तमिलनाडु में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए विशेष आबंटन**

**1898 डा॰ वी॰ मैत्रेयनः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार द्वारा तमिलनाडु में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए कोई विशेष आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत चार वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत शीर्ष-वार तथा वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) क्या सरकार की रेलवे की भूमि के किसी वाणिज्यिक उपयोग करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

तमिलनाडु में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए विशेष आबंटन के संबंध में 28.12.2018 को राज्‍य सभा में डा॰ वी॰ मैत्रेयन के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1898 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) और (ख): परियोजनाओं के लिए निधि का आबंटन जोनल रेलवे-वार किया जाता है। कुछ रेल परियोजनाएं एक से अधिक राज्यों में फैली होती हैं।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 11,405 करोड़ रुपए की लागत पर 08 नई लाइन परियोजनाएं, जिसकी कुल लंबाई 849 किमी है, 4,667 करोड़ रु. की लागत पर 05 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनकी कुल लंबाई 1,051 किमी है और 5,718 करोड़ रुपए की लागत पर 09 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनकी कुल लंबाई 596 किमी है, योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 21,790 करोड़ रु. है।

 विगत वर्षों में इन परियोजनाओं के संबंध में परियोजना-वार ब्यौरा, जिसमें इन पर किया गया व्यय तथा इनके लिए किया गया बजट आबंटन शामिल है, का ब्यौरा संसद में प्रस्तुत बजट प्रलेखों में उपलब्ध है और यह ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट (अर्थात [www.indianrailways.gov.in](http://www.indianrailways.gov.in)) पर भी उपलब्ध है।

(ग): ऐसी खाली पड़ी रेलवे भूमि, जिसकी रेलवे के अवसंरचना विकास के लिए निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं हो और जो वाणिज्यिक विकास के लिए उपयुक्त भी हो, को इस प्रयोजन के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को सौंपा जाता है। तमिलनाडु राज्य में 35.46 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक विकास के लिए आरएलडीए को सौंपी गई है।

\*\*\*\*\*\*